



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रतिष्ठान से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 1987/फाल्गुन 27, 1908

No. 55]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 1987/PHALGUNA 27, 1908

कानून, लोक शिक्षा तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1987

संकल्प

सं. 2/13/87-पी.आई.सी.—वित्त मंत्रालय के दिनांक 8 नवम्बर, 1985 के संकल्प संख्या 5(56)-ई-111/83 द्वारा बोधे केन्द्रीय वेतन आयोग के यथा संशोधित विचारार्थ विषयों के संबंध में आयोग ने प्रेषित भारतीय सेवाओं के सदस्यों तथा सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों, तथा संघ शासित क्षेत्रों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विद्यमान तथा भावी—बोनों प्रकार के पेंशनभोगियों के लिए पेंशन के ढांचे तथा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं के संबंध में अपनी रिपोर्ट का भाग II, 12 दिसम्बर, 1986 को प्रस्तुत किया था।

2. सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और साथ ही यह निर्णय किया है कि इन सिफारिशों को, कुछेक बातों के संबंध में कुछ संशोधनों के साथ व्यापक रूप में स्वीकार कर लिया जाए, उदाहरण के तौर पर ;

- आयोग द्वारा सिफारिश की गई रु. 300/- प्रतिमाह की बजाए न्यूनतम पेंशन तथा न्यूनतम परिवार पेंशन रु. 375 प्रति माह होगी।
- संशोधित वेतनमानों के अनुसार परिवार पेंशन की दरें निम्न प्रकार संशोधित कर दी जाएगी:—

आयोग द्वारा यथा-संस्तुत		सरकार द्वारा यथा संशोधित	
संशोधित वेतनमान में वेतन	परिवार पेंशन की मासिक दर	संशोधित वेतनमान में वेतन	परिवार पेंशन की मासिक दर
(क) रु. 1500 और उससे कम	वेतन का 30% परन्तु शर्त यह है कि यह राशि न्यूनतम रु. 300 होगी।	रु. 1500 तक	वेतन का 30% परन्तु शर्त यह है कि यह राशि न्यूनतम रु. 375 होगी।
(ख) रु. 1500 से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत परन्तु शर्त यह है कि राशि न्यूनतम रु. 450 और अधिकतम 1000 होगी।	रु. 1501 से 3000 तक	वेतन का 20% परन्तु शर्त यह है कि यह राशि न्यूनतम रु. 450 होगी।
		रु. 3000 से अधिक	वेतन का 15% परन्तु शर्त यह है कि यह राशि न्यूनतम रु. 600 और अधिकतम रु. 1250 होगी।

(iii) सरासरी बलों के कामियों के लिए व्यवस्था तब की दूर निम्न प्रकार संशोधित की जाएगी :

प्रायोग द्वारा यथासंस्तुत		सरकार द्वारा यथासंशोधित	
रैंक	राशि प्रतिमाह	रैंक	राशि प्रतिमाह
अधिकारी और कमीशन प्राप्त अधिकारी	रु. 600	अधिकारी और कमीशन प्राप्त अधिकारी	रु. 750
कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी, अधिकारी स्तर से नीचे के कामिक और गैर-योद्धा (पंजीकृत) कामिक	रु. 450	जे. सी. ओ. अन्य रैंक तथा एन. सी. (ई)	रु. 550 रु. 450

(iv) अब सेवा निवृत्ति की अधिकतम राशि एक लाख रुपये होगी और सेवा निवृत्ति उपदान की गणना के लिए गणना योग्य अवधि में कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी।

प्रायोग की विस्तृत सिफारिशों और सरकार द्वारा उन पर लिए गए निर्णय इस संकल्प के साथ संलग्न विवरण में दिये गए हैं। प्रायोग द्वारा की गई ऐसी सिफारिशें जिन्हें इस अनुबन्ध में शामिल नहीं किया गया है, सरकार द्वारा उनकी जांच की जा रही है और इन पर यथा संभव शीघ्र निर्णय लिए जाएंगे।

3. भारत सरकार, विभिन्न जटिल विषयों पर प्रायोग द्वारा किए गए कार्य तथा प्रस्तुत की गई महत्वपूर्ण रिपोर्ट के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों तथा सभी अन्य संबंधित व्यक्तियों को भेज दी जाए।

आई. के. रतगीला, अपर सचिव

अनुबन्ध

अनुबन्ध केन्द्रीय वेतन प्रायोग की रिपोर्ट के भाग-II में वर्तमान तथा भावी पेंशनभोगियों के पेंशन आने से संबंधित प्रायोग की सिफारिशों तथा उन पर सरकार के निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	सिफारिश (रिपोर्ट के पैराग्राफ का नुमांदा कोष्ठकों में दिया गया है)	सरकार के निर्णय
1	2	3
1. परिलब्धियां		
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति अनुबन्धियों की गणना के लिए गणना योग्य परिलब्धियां मूल नियम 9(21) (क) (i) (5.21) में यथापरिभाषित मूल वेतन होना चाहिए।	स्वीकार की जाती है।
2. पेंशन		
(i)	10 वर्षों से नीचे की ग्रहक सेवा के लिए एकमुश्त सेवा उपदान के भुगतान की विद्यमान पद्धति और 10 वर्षों और अधिक की ग्रहक सेवा के लिए मासिक पेंशन जारी रहे। (5.12)	स्वीकार की जाती है।
(ii)	10 वर्ष से कम की ग्रहक सेवा के लिए अनुमेय सेवा उपदान की दर ग्रहक सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए आधे महीने के वेतन की एक समान दर के रूप में परिभाषित कर दी जाए। (5.23)	स्वीकार की जाती है।
(iii)	विद्यमान नियम जिनके अधीन पेंशन की गणना सेवा के पिछले 10 महीनों के दौरान की गई औसत परिलब्धियों के संघर्ष में की जाती है जारी रहे। (5.15)	स्वीकार की जाती है।
(iv)	सरासरी सेवा कामियों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मूल पेंशन की अधिकतम राशि भविष्य में 4500 रुपये प्रतिमाह होनी चाहिए। (5.20 13.10)	स्वीकार की जाती है।

1	2	3
(v) सरकार बर्खास्त किए गए प्रथमा सेवा से हटाए गए व्यक्तियों को अनुकम्पा के आधार पर संभर की जाने वाली पेंशन की सादृश्यता पर सेवा से त्यागपत्र देने वालों को अनुचित सेवान्त प्रमुविधायें देने पर विचार करें। (5.14)		स्वीकार नहीं की गई।
(vi) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए पेंशन, जो इस समय स्लैब पद्धति के रूप में गिनी जा रही है उसे औसत वेतन के 50 प्रतिशत पर गिना जाए। (5.18)		स्वीकार की जाती है।
3. मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान		
(i) सेवानिवृत्ति पर मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान के भुगतान को शामिल करने वाले विद्यमान उपबंधों की विद्यमान ऊपरी सीमा के साथ जारी रखा जाए। (5.27)		इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि धन सम्बन्धी ऊपरी सीमा को बढ़ाकर एक लाख किया जाएगा तथा सेवा निवृत्ति उपदान की गणना के लिए गिने वाले योग्य परिसम्पत्तियों की कोई सीमा नहीं होगी।
(ii) मृत्यु हो जाने पर मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान को निम्न प्रकार विनियमित किया जाए:		स्वीकार की जाती है।
सेवा	दर	
(i) 1 वर्ष से कम	वेतन का दशगुना	} वर्तमान दरों के समान ही।
(ii) 1 वर्ष परन्तु 5 वर्ष से कम	वेतन का छह गुना	
(iii) 5 वर्ष परन्तु 20 वर्ष से कम	वेतन का 12 गुना	
(iv) 20 वर्ष अथवा उससे अधिक		सेवा की प्रत्येक पूरी छमाही के लिए आधे मास का वेतन किन्तु शर्त यह कि अधिकतम राशि वेतन का 33 गुना होगी और इसकी आर्थिक सीमा एक लाख रुपए होगी। गिने जाने योग्य वेतन की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगा (6.11)
4. परिवार पेंशन		
(i) इस बात पर विचार करते हुए कि आयोग द्वारा विकारिण की गई संशोधित पेंशन संरचना 608 तक के औसत सूचकांक से जुड़ी है, वेतन रेंज तथा परिवार पेंशन की दरें निम्न प्रकार संशोधित की जाए—		परिवार पेंशन की दरें निम्न प्रकार संशोधित की जाती हैं :— संशोधित वेतनमान में वेतन परिवार पेंशन की मासिक दरें
संशोधित वेतनमान में वेतन	परिवार पेंशन की मासिक दर	
(क) रु. 1500 अथवा उससे कम	वेतन का 30% परन्तु शर्त यह है कि राशि न्यूनतम रु. 300 होगी।	रु. 1500 तक वेतन का 30% परन्तु शर्त यह है कि यह राशि न्यूनतम 375/- रु. होगी।
(ख) रु. 1500 से अधिक	वेतन 15% परन्तु शर्त यह है कि यह राशि न्यूनतम 450 रु. तथा अधिकतम रु. 1000 होगी (6.8)	रु. 3000/- से अधिक वेतन का 20% परन्तु शर्त यह है कि यह राशि न्यूनतम 450/- रु. होगी।
		वेतन का 15% परन्तु शर्त यह है कि यह राशि न्यूनतम 600/- रु. तथा अधिकतम रु. 1250/- होगी।
(ii) 7 वर्षों की अवधि के लिए या उस तारीख तक जिस तारीख को विद्यमान सरकारी कर्मचारी ने 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होगी, यदि वह जोषित होता, इनमें जो भी कम हो, उच्चतर दरों पर परिवार पेंशन के भुगतान की विद्यमान व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। (6.8)		स्वीकार की जाती है।
5. अस्थायी तथा स्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों के लिए सेवान्त प्रमुविधायें		
(i) ऐसे स्थायी रूप तथा अस्थायी सरकारी कर्मचारी जो अधिकतमता की धार्य पर सेवानिवृत्त होने वाले हैं प्रथमा जिन कर्मचारियों को कम से कम 10 वर्ष की सेवा के बाद समुचित निकटता प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा के लिए स्थायी रूप से अधिनियमित कर दिया गया हो उन्हें पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान जैसे सेवानिवृत्ति के लाभ उसी प्रकार से प्राप्त होंगे जो केन्द्रीय निवृत्ति सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन स्थायी रोजगार के कर्मचारियों को अनुभूत होते हैं। (5.30)		स्वीकार की जाती है।

1

2

3

- (ii) स्थायीयत् और अस्थायी कर्मचारी जिनकी सेवाकाज में ही मृत्यु हो जाती है स्वीकार की जाती है। उनके परिवारों को मृत्यु से संबंधित वही लाभ दिए जाएं जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन उनकी सेवा अवधि पर विचार किए बिना, स्थायी कर्मचारियों के परिवारों को अनुज्ञेय होते हैं। (6.12)

6. असाधारण पेंशन नियमावली (सिविल)

- (i) 100 प्रतिशत असम्यक्ता के लिए असम्यक्ता पेंशन, परिवार पेंशन को साधारण स्वीकार की जाती है। वरों के अनुरूप हो सकती है। (7.12)
- (ii) जहां स्थायी असम्यक्ता 60 प्रतिशत से कम नहीं है उसमें कुल पेंशन (पेंशन नियमों के अधीन अनुज्ञेय, सेवा पेंशन/उपदान ई. प्रो. सी. नियमों के अधीन असम्यक्ता को मिलाकर मूल वेतन के 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, किन्तु शर्त यह है कि वह न्यूनतम 750/- रुपए और अधिकतम 2500 रुपए हो। (7.12)
- (iii) ऐसे सरकारी कर्मचारी जो सेवा के कारण ही असम्यक् हुए हैं, उनके लिए कुत्रिम भंग, पेसनेकर और बैसाखियों जैसे विशेष सहायक उपकरणों की व्यवस्था की जाए और उन्हें बाव में सरकारी लागत पर बरबलवाया जाए। (7.13)
- (iv) विधवा कर्मचारी की विधवा/विधुर तथा बच्चों के लिए प्रत्येक से परिवार पेंशन स्वीकार की जाती है। मंजूर करने की पद्धति—बास पेंशन/प्रत्येक बच्चे को संतान शिक्षा भत्ता, बंद कर दिया जाना चाहिए और इसके स्थान पर, पेंशन नियमों के अधीन, परिवार पेंशन के आधार पर, बरिष्ठतम लाभभोगी को बेय एक समेकित पेंशन की पद्धति लागू की जाए। (7.10)
- (v) समेकित परिवार पेंशन की दर जिसमें बच्चों की पेंशन और संतान शिक्षा भत्ते का तब शामिल है इस बात पर विचार किए बिना, इस प्रकार परिशिष्टित की जानी चाहिए कि मृतक ने सेवा के 7 वर्ष पूरे किए हैं या नहीं।— स्वीकार की जाती है।
- (क) जहां विधवा सरकारी कर्मचारी कोई पेंशनी पद धारित नहीं कर रहा था।
- (i) यदि विधवा संतान विहीन है पेंशन नियमों के अधीन कुटुम्ब पेंशन के लिए निर्धारित साधारण दरों पर।
- (ii) यदि विधवा के संतान/संताने वेतन का 40 प्रतिशत न्यूनतम 500/- रुपए, अधिकतम 1500/- रुपए।
- (ख) जहां विधवा सरकारी कर्मचारी कोई पेंशनी पद धारित कर रहा था।
- (i) यदि विधवा संतान विहीन है पेंशन नियमों के अधीन कुटुम्ब पेंशन के लिए निर्धारित उच्चतर दरों पर।
- (ii) यदि विधवा के संतान/संताने वेतन का 60 प्रतिशत न्यूनतम 750/- रुपए, अधिकतम 2500/- रुपए।

उक्त क (i) तथा (ख) (i) में दर्शायी गई दरों पर कुटुम्ब पेंशन का भुगतान विधवा को उसकी मृत्यु अवधि पुनर्विवाह तक इसमें से जो भी पहले हो किया जाए। उपर्युक्त क (ii) तथा ख(ii) में दर्शायी गई दरों पर कुटुम्ब पेंशन विधवा को तब तक दी जाए जब तक कि उसकी संतान/संतानें कुटुम्ब पेंशन नियमों के अधीन निर्धारित भत्ता प्राप्त नहीं कर लेती और उसके पश्चात् विधवा को उपर्युक्त क(i) तथा ख(i) में दर्शायी गई दरों पर कुटुम्ब पेंशन का भुगतान किया जाए।

ऐसे मामलों में जहां विधवा को मृत्यु हो जाती है या वह पुनर्विवाह कर लेती है, तो उसकी संतानों को उपर्युक्त (क) तथा ख(i) में दर्शायी गई दरों पर कुटुम्ब पेंशन का भुगतान किया जाए और ऐसी ही समान दरें पिता विहीन/माता विहीन संतानों पर भी लागू की जाएं। दोनों ही मामलों में संतानों को कुटुम्ब पेंशन तब तक दी जाए जब तक कि वे कुटुम्ब पेंशन नियमों के अधीन निर्धारित भत्ता प्राप्त नहीं कर लेती।

1	2	3
	<p>ऊपर सिफारिश की गई कुटुम्ब पेंशन की समेकित दरों के प्रतिरिक्त किसी संतान पेंशन भ्रमबा शिवा भले का भुगतान न किया जाए। आश्रित माता पिता, भाइयों, बहनों आदि को, विशिष्ट शर्तों के अधधीन, पिताविहीन/माताविहीन संतानों पर जो दरें लागू हैं उससे प्राधी दरों पर कुटुम्ब पेंशन दी जाए। (7.11)</p>	
7. उदारीकृत पेंशन संबंधी एवार्बः		
(i) विभिन्न दरों पर कुटुम्ब पेंशन की भंजरी के लिए रु. 700 प्रतिमास की विद्यमान वेतन सीमा को आयोग द्वारा सिफारिश किए गए संशोधित वेतन ठाँके के अनुसार संशोधित करके रुपए 2200 प्रतिमास किया जाए। (7.18)	ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिनकी उग्रवादियों, डाकुओं, तस्करों तथा असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हमले किए जाते अथवा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है, विधवा को, उस समय तक जब कि वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती/उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, विवंगत सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के बराबर कुटुम्ब पेंशन अनुमत होगी।	
(ii) संतान भत्ता तथा संतान शिक्षा भत्ता दोनों को मिला दिया जाए और प्रत्येक संतान को निम्नलिखित दरों पर एक समेकित भत्ता अनुमत किया जाए :—	स्वीकार की जाती है। संतान भत्ता उस समय तक अनुज्ञेय नहीं होगा जब तक कि माना को विवंगत सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के बराबर कुटुम्ब पेंशन अनुमत्य है।	
(i) जहां विवंगत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय उसका वेतन रुपए 2200 प्रतिमास से कम हो	रु. 100 प्रतिमास प्रति संतान	
(ii) रुपये 2200 तथा उससे अधिक यदि विधवा पुनर्विवाह कर लेती है तो संतानों को ऊपर बताए अनुसार संतान भत्ता दिया जाए। (7.19)	रु. 100 प्रतिमास प्रति संतान	
(iii) माताविहीन संतानों को सामूहिक रूप से पेंशन नियमों के अधधीन कुटुम्ब पेंशन की सामान्य दरों पर कुटुम्ब पेंशन दी जाए और इसके प्रतिरिक्त वे, उपर बताए अनुसार संतान भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। (7.20)	स्वीकार की जाती है।	
8. सशस्त्र सेना कर्मिक :		
(i) प्रत्येक ऐसे अधिकारी की सेवानिवृत्ति पेंशन, जिसने पेंशन का पात्र होने के लिए निर्धारित सेवा पूरी कर ली है, उसके वेतन तथा उसके द्वारा की गई वास्तविक अर्हक सेवा के आधार पर होनी चाहिए फिलहाल अनुज्ञेय सेवा में जोड़े जाने वाले लाभ को इस शर्त के अधधीन जारी रखा जाए कि लाभ जोड़ने के बाद कुल अर्हक सेवा 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी। (13.8)	स्वीकार की जाती है।	
(ii) अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मिकों के लिए विद्यमान लाभ सहित विभिन्न वेतन समूहों में प्रत्येक रैंक के लिए पेंशन की मानक दर की वर्तमान प्रणाली को जारी रखा जाए। (13.9)	स्वीकार की जाती है।	
(iii) पेंशन के प्रयोजन अर्हक से सेवा का हिसाब लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार के अधधीन सिविल विभाग अथवा सशस्त्र सेना में की गई कमीशन-पूर्व की पूरी सेवा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पेंशन की अनुज्ञेयता के लिए संतोषप्रव सेवा के प्रमाण पत्र की अपेक्षाओं को भी समाप्त कर दिया जाए। (13.11)	स्वीकार की जाती है।	
(iv) सशस्त्र सेनाओं के कर्मिकों की सेवा, यहां तक कि कणामूलक आधार पर/वैयक्तिक कारणों से बर्खास्त कर दिए जाने अथवा बिना कटौती से समयपूर्व सेवानिवृत्ति, चाहे सेवानिवृत्ति किसी भी प्रकार की रही हो, के मामले में, प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक मास के वेतन की एक समान दर से सेवानिवृत्ति/सेवा-उपदान अदा किया जाए। (13.14)	स्वीकार की जाती है, सिवाय उसके कि सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक मास के वेतन के स्थान पर अर्हक सेवा की प्रत्येक पूरी छिमाही अवधि के लिए आधे मास के वेतन पर उपदान का हिसाब लगाया जाएगा।	
(v) सशस्त्र सेनाओं के कर्मिकों का मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान निर्धारित करते के उद्देश से वास्तविक अर्हक सेवा में 5 वर्ष का लाभ जोड़ा जाए, बशर्त कि वास्तविक अर्हक सेवा तथा लाभ को जोड़कर सेवा 33 वर्ष से अधिक न बढ़ जाए। (13.15)	स्वीकार की जाती है।	

1

2

3

(vi) अधिक सेवा से इतर कारणों से हुई अशक्तता के मामले में असमर्थता पेंशन का सेवातत्त्व अशक्तता पेंशन के बराबर ही होना चाहिए । (13.25)

(vii) पेंशन, सेवा के पिछले 10 मासों के दौरान लिए गए वेतन के 50 प्रतिशत के हिसाब से ही मिली जाए । वेतन का तत्पर्य केवल मूल वेतन से है, जिसे मूल नियम 9(21) (क) (1) के अधीन परिभाषित किया गया है । सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के मामले में, इसमें रैंक से संबंधित वेतन भी शामिल किया जाएगा । (13.10, 5.15, 5.19, 5.21)

(viii) सिविल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उत्पन्न से संबंधित मिफारिशें सशस्त्र सेनाओं के कामियों पर भी लागू होंगी । (13.15 5.27, 6.11)

(ix) जिन कर्मचारी की सैनिक सेवा के कारण हुई अथवा बढ़ गई क्षति से इतर कारणों से सेवा के दौरान अथवा सेवा से अलग होने के बाद मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को साधारण परिवार पेंशन के मामले में अध्याय 6 में सिविल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन के बारे में की गई मिफारिशें सशस्त्र सेनाओं के कामियों पर भी लागू होंगी (13.26, 6.8)

(x) अधिकारियों तथा अधिकारी रैंक से नीचे के कामियों—दोनों के लिए ही सेवा तत्त्व अशक्तता के समय अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति पेंशन पर नियत किया जाए और इसमें सेवा लाभ जोड़ा जाए भले ही सेवा की वास्तविक अवधि पेंशन के लिए अर्हक सेवा न बनती हो । अधिकारी रैंक से नीचे के कामियों के मामले में, सेवा तत्त्व रैंक की न्यूनतम सेवानिवृत्ति पेंशन के बोनिटिहई से कम न करना ही जारी रखा जाए । (13.18)

(xi) जब अशक्तता स्थायी मानी जाए किन्तु कर्मचारी को सेवा में रख लिया गया गया हो तो अशक्तता तत्त्व के 100% संशोधित मूल्य का सुगतान किया जाए । (13.21)

(xii) जब बिकरसा बोर्ड की राय में स्थायी परिवार रखा जाना आवश्यक हो तो, लड़ाई तथा लड़ाई से इतर हुई अशक्तताओं दोनों के लिए, स्थायी परिवार भत्ते की एक समान दर ही रखी जाए । अधिकारी तथा अधिकारी रैंक नीचे के कामियों—दोनों के लिए 300 रुपए प्रतिमास की दर से भत्ता नियत किया जाए, बशर्ते कि सभी विद्यमान शर्तें पूरी होती हों । विद्यमान अशक्तता पेंशन होगी जो ऐसा भत्ता ले रहे हैं, उनको भी समान दर की अनुमति दी जाए । (13.24)

(xiii) अधिकारियों के लिए प्राप्ति पेंशन और अधिकारी रैंक से नीचे के कामियों के लिए द्वितीय जीवन एवार्ड की विद्यमान दरों को सरल बनाए जाने की आवश्यकता है । प्राप्ति पेंशन तथा द्वितीय जीवन एवार्ड, दिवंगत कर्मचारी की विधवा को अनुज्ञेय विशेष परिवार पेंशन की 50 प्रतिशत के हिसाब से मंजूर किया जाए, यदि प्राप्तकर्ता (माता-पिता अथवा माता-पिता के न रहने पर, भाई-बहन मुख्यतः दिवंगत कर्मचारी पर पूर्णतया निर्भर रहे हों और उन्हें आर्थिक आवश्यकता हो । इस प्रकार, "साधन सीमा" से संबंधित विद्यमान शर्तें समाप्त की जा सकती हैं । (13.31)

(xiv) उदासीन परिवार पेंशन संबंधी एवार्ड (लड़ाई विपदाएं) के अधीन अधिकारियों तथा अधिकारी रैंक से नीचे के कामियों दोनों के मामले में अंतिम वेतन के बराबर होनी चाहिए और बहु, विधवा/नामित वारिस को मृत्यु/अनर्हताओं तक मिलनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, कोई संतान भत्ता अथवा संतान शिक्षा भत्ता, भत्ता नहीं किया जाना चाहिए । (13.33)

(15) उनके मामलों में, जो कर्मचारी सैनिक सेवा के कारण हुई अथवा इस कारण बड़ी हुई क्षति के फलस्वरूप गुजर जाता है तो उनके परिवार को मंजूर की गई विशेष परिवार पेंशन के संबंध में सिविल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अध्याय 7 में की गई मिफारिशें, समेकित परिवार पेंशन जिसमें संतान पेंशन का तत्त्व और संतान शिक्षा भत्ता शामिल है, लागू होंगी चाहिए । (13.27, 7.10, 7.11, 7.13, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21)

स्वीकार की जाती है ।

स्वीकार की जाती है । जो संशोधित प्रावधान सिविल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं, वही रक्षा कामियों के मामले में भी लागू होंगे ।

स्वीकार की जाती है । जो संशोधित प्रावधान सिविल सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं, वही रक्षा कामियों के मामले में भी लागू होंगे ।

स्वीकार की जाती है । फिर भी फ्लाईंग/पैरा जम्पिंग इयूटी के दौरान अथवा सेवा के एयर क्राफ्ट में टेबलिंग इयूटी पर हुई अशक्तता के लिए न्यूनतम सेवा के विद्यमान उपबन्ध, अधिकारी रैंक के नीचे के कामियों के मामले में भी जारी रहेंगे ।

स्वीकार की जाती है ।

स्वीकार की जाती है ।

स्वीकार की जाती है । तथापि अधिकारी स्तर से नीचे के कामियों के मामले में, विशेष परिवार पेंशन के प्रथम एवार्ड के लिए, परिवार के किसी एक पालन संवस्य को नामित करने की मौजूदा व्यवस्थाएं उस वक्ता में जबकि माता-पिता की मृत्यु हो गई हो, जहां ये मूल एवार्ड प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किए गए थे तथा उनकी, विधवा की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना, विशेष परिवार पेंशन पूरी स्थानान्तरित करनी जारी रखी जाए ।

स्वीकार की जाती है ।

स्वीकार की जाती है । अन्यायविधि कमोशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमोशन प्राप्त अधिकारियों के परिवारों को भी जिनकी सैनिक सेवा के कारण अथवा इस कारण बड़ी हुई क्षति के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है, विशेष परिवार पेंशन प्रादि के लाभ दिए जाएंगे ।

स्वीकार की जाती है ।

1

2

3

(16) 100 प्रतिशत अशक्तता के लिए, अशक्तता तत्व की विद्यमान दरों को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :—

रैंक	राशि प्रति मास
अधिकारी और आनरेरी कमीशनप्राप्त अधिकारी	रु. 600/-
कनिष्ठ कमीशनप्राप्त अधिकारी, अधिकारी रैंक से नीचे के रु.	450/-
कामिक और गैर-योजना (पंजीकृत)	

100 प्रतिशत से कम तथा 20 प्रतिशत तक की अशक्तताओं के लिए, उपर्युक्त दरों में आनुपातिक कटौती की जाए। अशक्तता तत्व की संशोधित दरों को, सभी विद्यमान अशक्तता पेंशन-भोगियों के मामले में लागू किया जाए। (13.20)

(17) 100 प्रतिशत के लिए युद्धभूमि वेतन अशक्तता की तारीख को लिए गए अन्तिम वेतन के बराबर रखी जाए। राशन के बढ़ने में कोई राशि शामिल नहीं करनी चाहिए। 20 प्रतिशत तक की कम आवश्यकताओं के लिए, युद्धभूमि वेतन में आनुपातिक कटौती कर दी जाए। (13.35)

स्वीकार की जाती है। अशक्तता तत्व की दरें निम्नानुसार संशोधित की जाएगी :—

अधिकारी तथा आनरेरी कमीशन प्राप्त अधिकारी रु.	750/-
जें. सौ. ओज	रु. 550/-
ओ आरन तथा एन. सीज (ई.)	रु. 450/-

स्वीकार की जाती है। सिवाय इसके कि 100 प्रतिशत से कम की अशक्तता के लिए युद्धभूमि वेतन, अधिकारियों के लिए अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए गए अन्तिम वेतन का 60 प्रतिशत और अधिकारी रैंक से नीचे के कामिकों के लिए 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

(18) अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्त प्रत्येक पूरे वर्ष की सेवा के लिए एक मास के वेतन के बराबर दिया जाए। (13.36)

स्वीकार की जाती है।

9. विद्यमान पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त लाभ

- (1) रक्षा पेंशन भोगियों, कुटुम्ब पेंशनभोगियों और असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों सहित; विद्यमान पेंशनभोगियों को निम्नानुसार अतिरिक्त राहत संभूत की जाए :

पेंशनभोगियों के व्योरे	500/- रु. पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त राहत	500/- रु. से ऊपर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त राहत
1	2	3
(1) वे पेंशनभोगी जिनका मंहगार्ड भत्ता पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के विनॉक 4 मार्च, 1986 के का. शा. सं. 42(4)/पेंशन तथा पेंशनभोगी/86 द्वारा विनियमित की जाती है; कुटुम्ब पेंशन-भोगी तथा वे जो असाधारण पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।	राहत सहित पेंशन की एकल राशि का 15 प्रतिशत जो कि न्यूनतम 75/- रुपये होगी।	638 रुपये की नियत राहत तथा पेंशन के 95 प्रतिशत पर संगणित परिकल्पित राहत के बीच का अन्तर जो कि 638 से कम से कम 175 रुपए ज्यादा होगी।
(2) वे जिनकी मंहगार्ड राहत उक्त कार्यालय स्थापन की तालिका II द्वारा विनियमित की जाती है।	राहत सहित पेंशन की सकल राशि का 10 प्रतिशत, जो कि कम से कम 50/- रुपये होगा।	538/- रुपये की नियत राहत तथा पेंशन के 80 प्रतिशत पर संगणित परिकल्पित राहत के बीच का अन्तर जो कि 538 से कम से कम 125/- रुपये ज्यादा होगी।
(3) वे जिनकी मंहगार्ड राहत उक्त कार्यालय स्थापन की तालिका III द्वारा विनियमित की जाती है।	—यथोपरि—	463/- रुपये की नियत राहत तथा पेंशन के 70 प्रतिशत पर संगणित परिकल्पित राहत के बीच का अन्तर जो कि 463 से कम से कम 100/- रुपये ज्यादा होगी। (10.14, 10.15, 10.16)
(ii) सनैब प्रणाली की बजाय औसत परिवर्धियों के 50 प्रतिशत पर पेंशन की गणना का लाभ सभी मौजूदा पेंशन भोगियों को भी अनुज्ञेय होना चाहिए और कामिक राहत सहित पेंशन पर अधिकतम सीमा 31 मार्च, 1985 से पहले सेवा-निवृत्त हुए व्यक्तियों पर लागू नहीं होनी चाहिए फिर भी यह लाभ-उक्त सिफारिश की अतिरिक्त राहत की गणना करने के लिए हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए। (10.17)		स्वीकार की जाती है।

- (iii) 1-1-1986 से पहले सेवा निवृत्त होने वाले विद्यमान पेंशनभोगियों तथा स्वीकार की जाती है।
कुटुम्ब पेंशन-भोगियों के मामले में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 तक राहत
सहित विद्यमान पेंशन तथा उनके लिए आयो ग द्वारा सिफारिश किए गए अति-
रिक्त लाभों को जोड़कर, एक राशि में समेकित किया जाए जिसे उनके मामले
में 1-1-1986 से मूल पेंशन समझा जाए। (10.19)

- (iv) भविष्य में न्यूनतम पेंशन 300/- रुपये प्रतिमास होनी चाहिए। विद्यमान न्यूनतम पेंशन तथा न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन 375/- रु. प्रतिमास
पेंशनभोगियों के मामले में जहां, राहत तथा आयो ग द्वारा सिफारिश की गई होगी। यह पेंशन विद्यमान तथा भावी पेंशन-भोगियों पर
अतिरिक्त राहत सहित मौजूदा पेंशन 300/- रुपये से कम देती है वहां बढ़ा-
कर 300/- रुपये प्रतिमास कर दिया जाए। (10.17) भी लागू होगी।

- (v) ऐसे पेंशनभोगियों के मामले में जो 31 मार्च, 1985 को या इसके पश्चात्
सेवानिवृत्त हुए थे और जिन्हें पेंशन तथा पेंशन-भोगी कल्याण विभाग के दिनांक
21 जून, 1985 के का. शा. की शर्तों के अनुसार वैयक्तिक पेंशन मंजूर की
गई है, सरकार वैयक्तिक पेंशन की एवज में उपयुक्त समझे जाने वाले किसी
आधार पर कोई एक मुक्त राशि देने पर विचार कर सकती है ताकि आयो ग
द्वारा प्रस्तावित युक्तियुक्त पेंशन संरचना के रूप में, वैयक्तिक पेंशन एक अलग
पेंशन के अंश के रूप में जारी न रहने पाए। (10.20)

(10) पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई राहत योजना

- (i) सेवारत कार्मिकों के लिए लागू की गई मंहगाई राहत योजना के अनुसार पेंशन- स्वीकार की जाती है।
भोगियों को, भविष्य में एक वर्ष में दो बार निम्न द्रों पर मंहगाई राहत प्रदान
की जाए।

(क) 1750/- रुपये प्रतिमास तक पेंशन शन प्रतिशत निष्प्रभावन
प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी।

(ख) 1751/- रुपये से 3000/- रुपये 75 प्रतिशत निष्प्रभावन उपांतिक
तक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन- समायोजन की शर्त में अध्यधीन
भोगी

(ग) 3000/- रुपये से अधिक पेंशन 65 प्रतिशत निष्प्रभावन।
प्राप्त करने वाले पेंशन-भोगी।

प्रतिशतता को अगले पूर्णांक में बदलने की पद्धति बड़ी होगी जो कि सेवारत
कार्मिकों के लिए मंहगाई भत्ता योजना के लिए लागू है (11.7)

- (ii) विद्यमान पेंशनभोगी (अर्थात् जो 1-1-1986 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं) उप- स्वीकार की जाती है। वैयक्तिक पेंशन जो कि भासिक आधार
भोक्ता औसत सूचकांक 608 तक राहत उनके मामले में आयो ग द्वारा सिफारिश पर ही जारी रहेगी; वह मंहगाई राहत विनियमित करने के
किए गए अतिरिक्त लाभ, सहित उपभोक्ता औसत सूचकांक 608 के बाद लिए अलग रखी जानी जारी रहेगी।
पेंशन की समेकित राशि पर मंहगाई राहत पाने के हकदार होंगे (11.8)।

(11) अंशदायी भविष्य निधि लाभग्राही

- (i) अंशदायी भविष्य निधि के ऐसे सभी लाभग्राही जो एक जनवरी, 1986 को भी स्वीकार की जाती है।
सेवा में हैं उन्हें उसी तारीख से पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल समझ लिया
जाना चाहिए बशर्त कि वे विशेष रूप से अंशदायी भविष्य निधि योजना के
अंतर्गत रहने का अपना विकल्प न दें। अंशदायी भविष्य निधि के ऐसे लाभग्राही
जो उस योजना के अंतर्गत रहने का विकल्प देते हैं वे अपनी सेवानिवृत्ति पर
आयो ग द्वारा सिफारिश की गई अनुग्रह राशि के पात्र नहीं होंगे। (9.8)

- (ii) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की प्रमुखियाएं उन विभागों के अंशदायी भविष्य स्वीकार की जाती है।
निधि के लाभग्राहियों को दे दी जाएं, जहां अंशदायी भविष्य निधि के लाभ-
ग्राहियों को मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान प्रमुखियाएं अनुज्ञेय नहीं हैं। इसे रेल
विभाग की ही भांति किया जाए। (9.8)

1	2	3
---	---	---

12 लागू होने की तारीख :

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारी, अखिल स्वीकार की जाती है।

भारतीय सेवाओं के कामिक तथा सशस्त्र सेनाओं के कामिक भी शामिल हैं, मृत्यु एवं भेदानिवृत्ति प्रमुविधाएं तथा भ्रष्टाचार द्वारा प्रस्तावित पेंशनभोगियों के लिए व्यक्तिगत पेंशन संरचना 1-1-1986 से लागू की जाए। 1-1-1986 से 30-9-86 के बीच भेदानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों के मामले में सरकार यह विचार करे कि 31-12-85 तक उनके द्वारा लिए गए पूरे मंहगाई भत्ते को पेंशन सम्बन्धी प्रमुविधाओं के लिए वेतन के रूप में गिना जाए। (17.2)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioner's Welfare)

New Delhi, the 18th March, 1987

RESOLUTION

No.2/13/87-PIC.—The Fourth Central Pay Commission, on 12th December, 1986, submitted Part-II of its Report dealing with the pension structure for pensioners, both present and future, and death-cum-retirement benefits for Central Government employees including Union Territories, members of All India Services and personnel belonging to Armed Forces in response to its terms of reference as amended by the Ministry of Finance Resolution No. 5(56)-E.III/83 dated 8th November, 1985.

Government have carefully considered the recommendations of the Commission and have decided that the recommendations shall be accepted broadly subject to certain modifications in certain aspects, e.g.—

(i) The minimum pension and minimum family pension shall be Rs. 375/-per month as against Rs.300/- recommended by the Commission;

(ii) The rates of family pension with reference to the revised scales of pay shall be modified as follows :

As recommended by Commission

As modified by the Government

Pay in revised scale	Rate of family pension per month	Pay in revised scale	Rate of family pension per month
(a) Rs.1500/-and below	30% of pay subject to a minimum of Rs.300/-	Upto Rs.1500/-	30% of pay subject to a minimum of Rs.375/-
(b) Above Rs. 1500/-	15% of pay subject to a minimum of Rs.450/- and maximum of Rs.1000/-	Rs. 1501/- to Rs.3000/- Above Rs.3000/-	20% of pay subject to a minimum of Rs.450/- 15% of pay subject to a minimum of Rs.600/-and maximum of Rs. 1250/-

(iii) The rates of disability element for Armed Forces Personnel shall be modified as follows :

As recommended by Commission		As modified by the Government	
Rank	Amount per month	Rank	Amount per month
Officers & Honorary Commissioned Officers	Rs.600/-	Officers & Honorary Commissioned Officers	Rs. 750
Junior Commissioned Officers Personnel below officer rank and non-combatant (enrolled)	Rs.450/-	Junior Commissioned Officers	Rs. 550
		Other ranks and Non-combatant (enrolled)	Rs. 450

- (iv) The maximum amount of retirement gratuity will now be Rs.1 lakh and there will be no ceiling on reckonable emoluments for calculation of retirement gratuity.

Detailed recommendations of the Commission and the decisions taken thereon by the Government are listed in the statement annexed to this resolution. The recommendations made by the Commission, which are not included in the Annexure are being examined by the Government and decisions thereon will be taken as early as possible.

3. The Government of India wish to express their deep appreciation of the work done by the Commission in dealing with the various complicated issues involved and presenting a valuable Report.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of Union Territories and all other concerned.

I. K. RASGOTRA, Additional Secy.

ANNEXURE

Statement showing the recommendations of the Fourth Central Pay Commission relating to Pension Structure for Pensioners—present as well as future—contained in Part—II of their Report and decisions of Government thereon

Sl. No.	Recommendation (Ref. to paragraph of the Report given in brackets)	Decisions of Government
1	2	3
1.	EMOLUMENTS	
	Reckonable emoluments for purposes of calculating pension and other retirement benefits should be the basic pay as defined in FR 9(21) (a) (i). (5.21)	Accepted.
2.	PENSION	
	(i) Existing system of paying lumpsum gratuity for service below 10 years and monthly pension for qualifying service of 10 years and more may continue. (5.12)	Accepted.
	(ii) The rate of service gratuity admissible for qualifying service less than 10 years may be revised at a uniform rate of half month's pay for each completed six monthly period of qualifying service. (5.23)	Accepted.
	(iii) The existing rules under which pension is calculated with reference to average emoluments drawn during last 10 months of service may continue. (5.15)	Accepted.
	(iv) Basic pension for Central Government employees including Armed Forces personnel should be subject to a maximum of Rs. 4,500/-per mensem. (5.20, 13.10)	Accepted.

1	2	3
---	---	---

(v) Government may consider grant of suitable terminal benefits to those who resign from services on the analogy of grant of pensionary benefits on compassionate consideration to those dismissed or removed from service. (5.14) Not accepted.

(vi) Pension may be calculated at 50% of the average pay for all categories of Central Government employees instead of being calculated on slab system as at present. (5.19) Accepted.

3. DCR GRATUITY

(i) Existing provisions governing payment of DCRG on retirement with existing ceiling may continue. (5.27) Accepted with the modification that the upper monetary ceiling shall be raised to Rs. one lakh and that there will be no ceiling on reckonable emoluments for calculation of gratuity on retirement.

(ii) DCRG in the event of death may be regulated as follows: Accepted.

Service	Rate
(i) Less than 1 year	2 times of pay
(ii) 1 year to less than 5 years	6 times of pay
(iii) 5 years to less than 20 years	12 times of pay
(iv) For service of 20 years or more	Half a month's pay for each completed six monthly period of service subject to a maximum of 33 times of pay and monetary limit of Rs. one lakh. There will not be upper limit on reckonable pay.

(6.11)

4. FAMILY PENSION

(i) Considering that the revised pay structure recommended by the Commission is linked to index average 608, pay ranges and rates of family pension may be revised as follows: The rates for family pension are modified as follows:

Pay in the revised scale	Rate of family pension per mensem	Pay in the revised scale	Rates of family pension per mensem
(a) Rs. 1500 and below	30% of pay subject to a minimum of Rs. 300/-	Upto Rs. 1500/-	30% of pay subject to a minimum of Rs. 375/-
(b) Above Rs. 1500/-	15% of pay subject to a minimum of Rs. 450/- and maximum of Rs. 1000/-	Rs. 1501/- to Rs. 3000/- Above Rs. 3000/-	20% of pay subject to a minimum of Rs. 450/- 15% of pay subject to a minimum of Rs. 600/- and maximum of Rs. 1250/-

(6.8)

1

2

3

- (ii) No change is necessary in the existing provisions for payment of family pension at enhanced rate for a period of 7 years or upto the date on which the deceased Government servant would have attained the age of 65 years had he survived, whichever is less. Accepted.
(6.8)

5. TERMINAL BENEFITS FOR TEMPORARY AND QUASI-PERMANENT EMPLOYEES

- (i) Quasi-permanent and temporary Government employees retiring at the age of superannuation or on being declared permanently incapacitated for further service by the appropriate medical authority after rendering service of not less than 10 years be paid retirement benefits like pension and DCR gratuity at the same scale as admissible to those in permanent employment under the CCS (Pension) Rules, 1972. Accepted.
(5.30)
- (ii) Families of quasi-permanent and temporary employees who die in harness may be allowed the same death benefits as admissible to families of permanent employees under the CCS (Pension) Rules, 1972 irrespective of length of service. Accepted.
(6.12)

6. EXTRAORDINARY PENSION RULES (CIVIL)

- (i) Disability pension for 100% disability may correspond to the ordinary rates of family pension. Accepted.
(7.12)
- (ii) Where permanent disability is not less than 60% the total pension (Service pension/gratuity admissible under pension rules plus disability pension under EOP rules) should not be less than 60% of basic pay subject to minimum Rs. 750/- and maximum of Rs. 2500/-. Accepted.
(7.12)
- (iii) Government employees, who are disabled due to causes attributable to service, may be provided special aids, such as artificial limbs, pacemaker, crutches and their replacement subsequently at government cost. Accepted in principle.
(7.13)
- (iv) The system of sanctioning separate family pension to the widow/widower and children pension/children's education allowance per child may be stopped and instead one consolidated pension payable to the senior most beneficiary at a time on the basis of a family pension under the pension rules may be introduced. Accepted.
(7.10)

1

2

3

- (v) The rates of the Consolidated family pension inclusive of element of children's pension and children education allowance may be revised as follows irrespective of whether the deceased had completed 7 years of service or not:—

Accepted.

- (A) Where the deceased government servant was not holding a pensionable post:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (i) If the widow is child-less | At the ordinary rates prescribed for family pension under the pension rules |
| (ii) If the widow has child/children | 40% of pay minimum Rs. 500/- maximum Rs. 1500/- |

- (B) Where the deceased government servant was holding a pensionable post:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (i) If the widow is child-less | At enhanced rates prescribed for family pension under the pension rules |
| (ii) If the widow has child/children | 60% of pay minimum Rs. 750/- maximum Rs. 2500/- |

Family pension at the rates indicated at (A) (i) and (b) (i) above may be paid to the widow upto the date of death or remarriage, whichever is earlier. Family pension at the rates indicated at (A) (ii) and (B) (ii) above may be paid to the widow till the child/children attain the age prescribed under the family pension rules and thereafter the widow may be paid family pension at rates indicated at (A) (i) and (B) (i) above.

In cases where the widow dies or remarries, the children may be paid family pension at the rates indicated at (A) (i) and (B) (i) above and the same rate may also apply to fatherless/motherless children. In both cases, family pension may be paid to the children till they attain the age prescribed under the family pension rules. No children's pension or education allowance may be paid in addition to the consolidated rates of family pension recommended above. The dependent parents, brothers, sisters etc., may be paid family pension at one-half of rate applicable to fatherless/motherless children subject to specified conditions.
(7.11)

7. LIBERALIZED PENSIONARY AWARDS

- | | |
|--|--|
| (i) The existing pay limit of Rs. 700/- p.m. for grant of family pension at different rates may be modified to Rs. 2200/- p.m. in terms of revised pay structure | In the case of government servants who while performing duties die as a result of attack by or during action against extremists, |
|--|--|

1

2

3

recommended by the Commission.
(7.18)

dacoits, smugglers and anti-social elements etc., the widow will be allowed family pension equal to last pay drawn by the deceased government servant until remarriage/death.

- (ii) The children's allowance and the children's education allowance may be merged together and a consolidated allowance may be allowed at the following rates per child :—

Accepted. Children's allowance will not be admissible so long as the mother is allowed family pension equal to last pay drawn of the deceased government servant.

- (i) Where pay of the deceased Rs. 100/- p.m. government servant is less than per child.
Rs. 2200/- p.m. at the time of death.

- (ii) Rs. 2200/- and above. Rs. 150/- p.m. per child.

The children's allowance as above may be paid to the children if the widow remarries.

(7.19)

- (iii) Motherless children together may be granted family pension at ordinary rates of family pension under pension rules and in addition draw children's allowance as above. (7.20)

Accepted.

8. ARMED FORCES PERSONNEL

- (i) Retiring pension for each officer who has completed the prescribed services for earning pension may be based on his pay and actual qualifying service rendered by him. The weightage of service, as presently admissible may continue subject to the condition that total qualifying service including weightage will not be more than 33 years.
(13.8)

Accepted.

- (ii) Existing system of standard rate of pension for each rank in the various pay groups with the existing weightage may continue for personnel below officer rank.
(13.9)

Accepted.

- (iii) Full pre-commissioned service rendered under the Central Government whether in civil department or in Armed Forces should be taken into account for working out the qualifying service for earning pension. The requirement of a satisfactory service certificate for admissibility of pension may also be dispensed with.
(13.11)

Accepted.

- (iv) Retiring/service gratuity may be paid at uniform rate of one month's pay for each complete year of service for Armed Forces Personnel even in cases of discharge on compassionate grounds/personal reasons or of premature retirement with no reduction irrespective of the type of retirement.
(13.14)

Accepted, except that instead of one month's pay for every completed year of service gratuity will be calculated at half-a-month's pay for each completed six monthly period of qualifying service.

1	2	3
(v) Weightage of 5 years may be added to the actual qualifying service for determining DCR gratuity of Armed Forces personnel subject to the actual qualifying service plus weightage not exceeding 33 years. (13.15)		Accepted.
(vi) In case of invalidment on account of causes not attributable to military service, invalid pension should be equal to service element of disability pension. (13.25)		Accepted.
(vii) Pension should be calculated at 50% of pay drawn during last 10 months of service. Pay means basic pay only as defined under FR 9(21)(a)(i). In case of officers in the Armed Forces it should include rank pay also. (13.10, 5.15, 5.19, 5.21)		Accepted.
(viii) The recommendations in regard to Death-cum-retirement gratuity for civil Central Government employees will also apply to Armed Forces Personnel. (13.15, 5.27, 6.11)		Accepted. Revised provisions decided to be applied to civilian Central Government servants will apply to defence personnel also.
(ix) Recommendations in regard to family pension for Civil Central Government employees in chapter 6 will also apply to Armed Forces Personnel in the matter of ordinary family pension granted to family of servicemen who die while in service or after discharge from service on account of causes which are neither attributable nor aggravated by military service. (13.26, 6.8)		Accepted. Revised provisions decided to be applied to Civilian Central Government employees will apply to defence personnel also.
(x) Service element both for officers and personnel below officer rank may be fixed at retiring pension admissible at the time of invalidment after including service weightage even if actual length of service does not qualify for pension. In the case of personnel below officer rank the service element may continue to be not less than 2/3 of the minimum retiring pension of the rank. (13.18)		Accepted. Existing provision of minimum service pension for disabilities sustained in flying/para-jumping duty or when travelling on duty in service aircraft will continue in the case of personnel below officer rank.
(xi) When the disability is assessed as permanent, but the individual is retained in service 100% commuted value of disability element may be paid. (13.21)		Accepted.
(xii) Where, in the opinion of the Medical Board, it is necessary to have a Constant Attendant, there may be a uniform rate of constant attendant allowance both for battle and non-battle casualties. The rate of allowance should be fixed at Rs. 300/- per month both for officers and personnel below officer rank, subject to fulfilling all existing conditions. Existing disability pensioners in receipt of this allowance may also be allowed the same rate. (13.24)		Accepted.

1

2

3

- (xiii) The existing rate of dependent's pension for officers and 2nd life award for personnel below officer rank need to be simplified. The dependent's pension and 2nd life award may be granted at 50% of the special family pension admissible to the widow of the deceased if the recipients (parents or in the absence of the parents, brothers and sisters) were largely dependent upon the deceased servicemen for support and are in pecuniary need. With this, the existing conditions regarding "means limit" may be dispensed with.
(13.31)

Accepted. However, in the case of personnel below officer rank, the existing provisions of nominating anyone of the eligible members of family for first award of special family pension and of transferring the special family pension in full to the widow regardless of her financial position in the event of death of parents, where they were nominated as the original awardees should be continued.

- (xiv) Under the liberalized family pensionary award (battle casualties) the special family pension should be equal to the last pay drawn both for officers & personnel below officer rank and the same should be admissible till death/disqualification of the widow/nominated heir. No children allowance or children education allowance should be paid in addition.
(13.33)

Accepted.

- (xv) In the matter of special family pension granted to family of servicemen who die on account of the causes which are attributable to or aggravated by military service, the recommendations made for Civil Central Government employees in chapter 7 for grant of consolidated family pension inclusive of element of Children's pension and children education allowance should apply.
(13.27, 7.10, 7.11, 7.13, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21)

Accepted. Families of Short Service Commissioned Officers and Emergency Commissioned Officers will also be extended the benefit of special family pension etc., where they die on account of causes attributable to or aggravated by military service.

- (xvi) The existing rate of disability element may be revised as follows for 100% disability:—

Accepted. The rates of disability element shall be modified as follows:—

Rank	Amount per mensem	Rank	Amount per mensem
Officers and Honorary Commissioned Officers	Rs. 600/-	Officers and Honorary Commissioned Officers	Rs. 750/-
Junior Commissioned Officer, personnel below officer rank and non-combatant (enrolled)	Rs. 450/-	Junior Commissioned Officers	Rs. 550/-
		Other ranks and non-combatant (enrolled)	Rs. 450/-

For disabilities less than 100% and upto 20%, the above rates may be reduced proportionately. The revised rates of disability element may be extended to all existing disability pensioners.
(13.20)

- (xvii) War Injury Pay for 100% disability may be equal to the last pay drawn on the date of invalidment. The amount in lieu of rations should not be included. For lower disability upto 20%, War Injury Pay may be reduced proportionately.
(13.35)

Accepted, except that for less than 100% disability the War Injury Pay shall not be less than 60% of last pay drawn for officers and 80% for personnel below officer rank.

1	2	3
(xviii)	Short Service Commissioned Officers should be paid terminal gratuity equal to one month's pay for each year for service. (13.36)	Accepted.
9. ADDITIONAL BENEFITS FOR EXISTING PENSIONERS		
(i)	Existing pensioners including defence pensioners, family pensioners and pensioners in receipt of extraordinary pension may be granted additional relief as follows :—	Accepted
Particulars of Pensioners	Additional relief for those drawing pensions upto Rs. 500/-	Additional relief for those drawing pension above Rs. 500/-
(i) Those whose dearness relief is regulated by Table-I of the D/P&PW O.M. No. 42(4)/P&PW/86, dated 4-3-1986; Family Pensioners and those in receipt of extraordinary pension.	15% of gross amount of pension, plus relief subject to a minimum of Rs. 75/-	Difference between fixed relief of Rs. 638/- and the national relief calculated at 95% of pension subject to a minimum increase of Rs. 175/- over Rs. 638/-
(ii) Those whose dearness relief is regulated by Table-II of the said O.M.	10% of gross amount of pension plus relief subject to a minimum of Rs. 50/-	Difference between fixed relief of Rs. 538/- and the national relief calculated at 80% of pension subject to a minimum increase of Rs. 125/- over Rs. 538/-
(iii) Those whose dearness relief is regulated by Table-III of the said O.M. (10.14, 10.15, 10.16)	-do-	Difference between fixed relief of Rs. 463/- and the national relief calculated at 70% of pension subject to a minimum increase of Rs. 100/- over Rs. 463/-

- (ii) The benefit of calculation of pension at 50% of average emoluments instead of slab system should also be admissible to all existing pensioners and the ceiling on pension plus graded relief should not apply to those who retired prior to March 31, 1985. This benefit shall not however, be taken into account for computation of additional relief recommended above.
(10.17)

Accepted.

1

2

3

- (iii) In the case of existing pensioners who retired prior to 1-1-1986 and family pensioners, their existing pension plus relief upto 608 CPI plus the additional benefits recommended for them by the Commission may be consolidated into one amount, which may be regarded as basic pension in their case from 1-1-1986. (10.19) Accepted.
- (iv) The minimum pension should be Rs. 300/- per mensem in future. In the case of existing pensioners, where the existing pension plus relief plus additional benefits recommended by the Commission fall short of Rs. 300/- the same should be stepped upto Rs. 300/- (10.18) The minimum pension and minimum family pension shall be Rs. 375/- per mensem. This will apply to existing as well as future pensioners.
- (v) In the case of pensioners who retired on or after 31-3-1985 and who have been granted personal pension in terms of Department of Pension and Pensioners' Welfare O.M. dated 21st June, 1985, Government may consider paying a lump sum amount in lieu of the personal pension on the basis considered appropriate so that this does not continue as a separate element in the rationalized pension structure suggested by the Commission. (10.20) Not accepted. Personal pension shall continue to be paid monthly. It will also not qualify for dearness relief beyond CPI 608.

10. DEARNESS RELIEF SCHEME FOR PENSIONERS

- (i) Pensioners may be granted dearness relief in future twice in a year in accordance with the scheme of dearness allowance introduced for serving personnel. Dearness relief may be allowed to pensioners at the following rates:— Accepted.
- (a) Those in receipt of 100% neutralization pension upto Rs. 1750/- p.m.
- (b) Those in receipt of pension between Rs. 1751/- to Rs. 3000/- } 75% neutralization } Subject to marginal adjustments
- (c) Those in receipt of pension above Rs. 3000/- } 65% neutralization }

The system of rounding of the percentages will be the same as applicable to dearness allowance scheme for in-service personnel.

(11.7)

- (ii) Existing pensioners (i.e. pre 1-1-1986 retirees) will be eligible for dearness relief beyond 608 points CPI, on the consolidated amount of pension plus relief upto 608 CPI plus the additional benefits recommended in their case by the Commission. (11.8) Accepted. The personal pension which will continue to be granted on monthly basis will continue to be excluded for regulating dearness relief.

1	2	3
---	---	---

11. CONTRIBUTED PROVIDENT FUND BENEFICIARIES

- (i) All CPF beneficiaries who are in service on 1-1-1986 Accepted.
should be deemed to have come over to the pension scheme on that date unless they specifically opt out to continue under CPF Scheme. The beneficiaries who decide to continue to remain under CPF Scheme should not be eligible for ex-gratia payment on their retirement recommended by the Commission.
(9.8)

- (ii) Benefits of death-cum-retirement gratuity may also be Accepted.
extended to CPF beneficiaries in Departments where the DCRG benefits are not admissible to CPF beneficiaries. This may be done on the same lines as in Railways.
(9.8)

12. DATE OF EFFECT

- Death-cum-retirement benefits for Central Government Accepted.
employees including employees of Union Territories, personnel belonging to All India Services and Armed Forces Personnel and the rationalized pension structure for pensioners proposed by the Commission may be made applicable with effect from January 1, 1986. In the case of employees retiring during the period from January 1, 1986 to September 30, 1986 the Government may consider treating the entire dearness allowance drawn by them upto December 31, 1985 as Pay for pensionary benefits.
(17.2)
-

